

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया पायलट योजना का शुभारंभ

10,000 बच्चों को सप्ताह में 5 दिन, प्रतिदिन 20 ग्राम की न्यूट्री बार आगामी 6 माह तक दी जाएगी

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विद्याधर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से बायोफोर्टीफाइड मिलेट न्यूट्री बार के पायलट वितरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। यह पहल 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति व उहराव बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस पायलट परियोजना के तहत जयपुर व उदयपुर जिलों के 544 चर्चयित आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 10,000 बच्चों को सप्ताह में 5 दिन, प्रतिदिन 20 ग्राम की न्यूट्री बार आगामी 6 माह तक दी जाएगी। न्यूट्री बार बायोफोर्टीफाइड बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद से तैयार की गई है, जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और ज़िंक जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'श्री अन्न योजना' से प्रेरित है। यदि पायलट



उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (बीच में) ने बायोफोर्टीफाइड मिलेट न्यूट्री बार के पायलट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

सफल होता है तो सीएसआर सहयोग से इसे राज्यभर में लागू किया जाएगा।"

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि एवं संस्था के सहयोग से यह नवाचार प्रारंभ हुआ है। जयपुर जिले के जयपुर प्रथम, सांगानेर ग्रामीण व उदयपुर जिले की आदिवासी परियोजना फलामिया को पायलट के लिए चुना गया है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह योजना न केवल बच्चों के पोषण स्तर को मज़बूत करेगी, बल्कि आंगनबाड़ी कार्यक्रमोंओं की भूमिका को भी सशक्त बनाएगी। उन्होंने इसे राजस्थान के आईसीडीएस कार्यक्रम में मिलेट आधारित खाद्य नवाचारों के समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विद्याधर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से बायोफोर्टीफाइड मिलेट न्यूट्री बार के पायलट वितरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया

सोनी, आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मलावत, से डॉ. तपन गोपे, के डॉ. अंकुर मुखर्जा, और हार्वेस्ट प्लस के रविंद्र ग़ोवर सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर के सेक्टर-8 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में हरियाली राजस्थान अभियान के अंतर्गत पौधापोषण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

श्री आर. दोरईस्वामी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ का कार्यभार संभाला

जयपुर। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, श्री आर. दोरईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ एवं एमडी) नियुक्त किया गया है।

मेयर पद से निलंबन के खिलाफ याचिका खारिज, तीन माह में न्यायिक जांच पूरी करने के निर्देश

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने पट्टा जारी करने की एवज में रिश्तत से जुड़े मामले में हेरिटेज नगर निगम की तत्कालीन मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका को खारिज कर दिया है। मुनेश ने अपने तीसरे निलंबन को चुनौती दी थी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही न्यायिक जांच तीन माह में पूरी की जाए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अनंतकाल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधि से गरिमा के साथ काम करने की उम्मीद की जाती है। प्रकरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र पेश किया गया है, जिसे समाज के कैसर के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी है और न्यायिक जांच में भाग लिया है, जिसका निर्णय आना अभी बाकी है। अदालत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह बड़ा चौकाने वाला है कि अदालती आदेश के बावजूद भी सरकार नौ माह तक निष्क्रिय रही और जांच प्रक्रिया कछुए की चाल के समान

■ हाईकोर्ट ने पट्टा जारी करने की एवज में रिश्तत से जुड़े मामले में हेरिटेज नगर निगम की तत्कालीन मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका को खारिज किया

रही। अदालत ने 1 दिसंबर, 2023 को एक माह में जांच पूरी करने को कहा था, लेकिन जून 2024 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। यह अवमानना की श्रेणी में आता है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को 5 अगस्त, 2023 को निर्लंबित किया गया था। जिस पर हाईकोर्ट की रोक लगने के बाद राज्य सरकार ने 1 सितंबर को निलंबन वापस ले गया। वहीं 22 सितंबर, 2023 को उसे पुनः निलंबित किया। जिसे 1 दिसंबर को अदालत ने रद्द कर नया जांच अधिकारी नियुक्त करने को कहा। याचिका में कहा गया कि स्वायत्त शासन विभाग ने 12 सितंबर, 2024 को याचिकाकर्ता को नोटिस देकर तीन दिन

में जवाब मांगा। जिस पर याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति पेश कर दी। वहीं 18 सितंबर को दूसरा नोटिस देकर जवाब मांगा। इस पर याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश मांगा। जिसे विभाग ने नोटिस का जवाब मानते हुए उसे 23 सितंबर, 2024 को निर्लंबित कर दिया। किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह से बिना सुनवाई का मौका दिए निर्लंबित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से एएजी जीएस गिल ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया है। याचिकाकर्ता ने नोटिस का जवाब देने के बजाए तकनीकी आपत्तियाँ दी थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ न्यायिक जांच लंबित है। एक बार न्यायिक जांच आरंभ होने के बाद प्रारंभिक जांच का कोई महत्व नहीं रहता है। याचिकाकर्ता ने न तो आरोप पत्र को चुनौती दी है और ना ही न्यायिक जांच की प्रक्रिया को, सिर्फ निलंबन को चुनौती दी गई है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए तीन माह में जांच पूरी करने को कहा है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों के कल्याण से जुड़े मामले में राज्य सरकार को अदालती आदेश की पालना में उठाए गए कदमों की जानकारी चार सप्ताह में सौंपने का आदेश देते हुए अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि ठोस जानकारी नहीं दी गई तो अदालत संबंधित विभागों के सचिवों को तलब करेगी। जस्टिस अरुणेश शिगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार ने पालना रिपोर्ट पेश की है, लेकिन इसमें सिर्फ खानपान्ही ही की गई है। रिपोर्ट में बजट आवंटन को लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, सिर्फ भविष्य में आवंटन की बात कही गई है। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बार बजट आवंटन हो गया तो फिर टेंडर जारी करने में अफसरों की भी मजा आएगा। न्यायमित्र ने अदालत को बताया कि एक ओर राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट में बिंदुवार दिए निर्देशों की पालना बताने में असमर्थ रही है, वहीं दूसरी ओर जिला जजों ने अपनी रिपोर्ट

■ अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि ठोस जानकारी नहीं दी गई तो अदालत संबंधित विभागों के सचिवों को तलब करेगी

में कई कमियाँ बताई हैं। लगभग सभी जेलों के भवन में सीलन आ रही है। कई जेलों की छतों से पानी टपक रहा है। एक जेल में तो सीवरेज का पानी भर रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि जेल, कारागृह है या सुधार गृह या नरकागृह। ऐसे हालातों में कोई अपराधी जेल में रहेगा तो वह सुधार नहीं सकता। वहीं खंडपीठ के जज भुवन गोयल ने कहा कि वे साल 1992 से जेलों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जेल के हालातों में सुधार नहीं मिल रहा है। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल को कहा कि फरीदाबाद स्थित जेल आदर्श जेल है। वहां दौरा कर सर्वे करना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को ठोस जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। गौरतलब है कि जेल के विकट हालातों पर अदालत ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा

जयपुर। दौलतपुरा थाना इलाके में स्थित अजमेर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार देर रात को तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारता हुआ निकल गया। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कांवर्टिया अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई और वहीं एक अन्य घायल का इलाज जारी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करावा कर परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामले की जांच पड़ताल सड़क दुर्घटना थाना (पश्चिम) पुलिस कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक और चालक कर रही है।

पुलिस के अनुसार हादसे में लक्ष्मीनारायणपुरा (दौलतपुरा) निवासी तुलसीराम सैनी (33) की मौत हो गई और वहीं पड़ोस में रहने वाला उसका दोस्त देवत राज चौधरी (32) घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि सोमवार देर रात तुलसीराम पड़ोस में रहने वाले दोस्त राज चौधरी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान थाना इलाके में स्थित एक्सप्रेस हाईवे पर पंखुड़ी होटल के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।

ऑनलाईन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार



पुलिस ने ठगी करने वाला साइबर ठग पल्ली वेंकट रामंजनैयुलू को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया।

(ग्रामीण) जिला कृष्णा, (आंध्र प्रदेश) को गिरफ्तार किया है।

फर्जी व्हाट्सएप नम्बर से सम्पर्क

से इन्वेस्टमेंट के फर्जी विज्ञापनों के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद एक वेबपेज का लिंक भेजकर रजिस्ट्रेशन

■ साइबर टीम ने हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना तक पीछा कर तकनीकी सहायता से आरोपित का मोबाइल ट्रैस कर आन्ध्रप्रदेश से पकड़ा

करवाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करवाते हुए इन्वेस्टमेंट की राशि विभिन्न बैंक खातों में डिपॉजिट करवाते हैं। डिपॉजिट राशि का लेनदेन वेबपेज पर दर्शाते हैं।और लोगों को विश्वास में लेकर प्रॉफिट का कुछ अमाउंट उनके खाते में ट्रांसफर भी करते हैं। जो किसी अन्य लोगों से ठगी गयी राशि का हिस्सा होता है।

कांग्रेस के पापों को धोने में लग रहा है समय, व्यक्तिगत नहीं, समान अवसर को मिलेगी प्राथमिकता : मदन राठौड़

- गहलोत ने अनियमित और अव्यवस्थित ढंग से बना दिए थे वार्ड व पंचायतें : मदन राठौड़
- कांग्रेसी नेताओं की आलोचनात्मक प्रवृत्ति, छिद्रान्वेषण और आलोचना करने के हैं आदी : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि "कांग्रेस ने जो पाप किए थे, उन पापों को धोने में समय लग रहा है।" गहलोत सरकार ने अनियमित और अव्यवस्थित ढंग से वार्ड और पंचायतों का गठन किया, कोई वार्ड 250 मतदाताओं का तो कोई 8000 मतदाताओं का बना दिया गया। अब भाजपा सरकार इन सभी गलतियों को सुधार कर व्यवस्थापन का कार्य कर रही है, जिससे सभी को समान अवसर मिल सके। किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए वार्ड या पंचायतों का गठन नहीं होना चाहिए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस की आलोचनात्मक प्रवृत्ति पर भी प्रहार किया और कहा कि "कांग्रेस को केवल छिद्रान्वेषण

और आलोचना की आदत हो गई है। जो हर समय नकारात्मक सोच के साथ रहते हैं। उन्हें अब सकारात्मक पहल करनी चाहिए।" भाजपा की सरकार पंचायत और निकाय चुनावों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। विधानसभा उपचुनाव और निकाय उपचुनावों के परिणामों का हवाला देते हुए मदन राठौड़ ने कहा, "36 में से 29 सीटें भाजपा ने जीती हैं, इसके बावजूद कांग्रेस खुद को विजयी बता रही है तो यह कांग्रेसियों के लिए चिंतन का विषय है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़

ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को जयपुर के दादिया क्षेत्र में सहकारिता विभाग के सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से सहकारिता विभाग से जुड़ी जनता पहुंचेगी और भाजपा कार्यकर्ता भी केंद्रीय मंत्री शाह से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। यह कार्यक्रम सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने और आमजन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। सहकारिता के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।

‘आदिवासी समाज के नाम पर भ्रम फैलाने घटिया कोशिश’

जयपुर। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि बांसवाड़ा-डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजकुमार रौत द्वारा जारी किया गया तथाकथित "भील प्रदेश" का नक्शा एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक स्टंट है। यह न केवल गौरवशाली राजस्थान की

■ अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि ठोस जानकारी नहीं दी गई तो अदालत संबंधित विभागों के सचिवों को तलब करेगी

एकता पर चोट है बल्कि आदिवासी समाज के नाम पर भ्रम फैलाने और सस्ती लोकप्रियता पाने की घटिया कोशिश भी है।राठौड़ ने कहा कि आज अगर कोई भील प्रदेश की बात करेगा, कल कोई मरू प्रदेश की मांग करेगा तो क्या हम अपने शानदार इतिहास, विरासत और गौरव को ऐसे ही टुकड़ों में बाँट देंगे?राठौड़ ने कहा कि सांसद राजकुमार रौत द्वारा जारी नक्शा आदिवासी समाज में जहर बोने की साजिश है जो प्रदेशद्रोह की श्रेणी में आता है और इसे जनमानस कभी स्वीकार नहीं करेगा।

देवनानी ने इंदौर में अत्याधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का अवलोकन किया

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मध्यप्रदेश यात्रा में इंदौर प्रवास के दौरान नगर निगम इंदौर द्वारा संचालित अत्याधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का अवलोकन किया। देवनानी ने इस प्लांट की कार्यप्रणाली और तकनीक की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल बेस्ट है। इंदौर नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कचरा निस्तारण, रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं एवं स्वच्छता मॉडल के विभिन्न पहलुओं के बारे में देवनानी को जानकारी दी।

देवनानी ने कहा कि इंदौर नगर निगम द्वारा विकसित यह वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली देशभर के लिए प्रेरणास्त्रोत है। यह न केवल कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करती है, बल्कि नगरीय जीवन को स्वस्थ, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। देवनानी ने कहा कि अजमेर नगर निगम सहित राज्य के विभिन्न शहरों में इसी मॉडल पर आधारित अत्याधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना हेतु प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए देवनानी राज्य सरकार से चर्चा करेंगे ताकि "स्वच्छ राजस्थान" का लक्ष्य प्रभावी रूप से

■ अजमेर नगर निगम सहित राजस्थान के विभिन्न शहरों में अत्याधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मॉडल लगाने के लिए राजस्थान सरकार से चर्चा करेंगे देवनानी

■ ‘जन जागरूकता, भागीदारी और सख्त निगरानी से हो सकता है समस्या का आसान हल’

साकार किया जा सके। देवनानी ने कहा कि कचरा निस्तारण की समस्या का समाधान आधुनिकतम तकनीक से होगा लेकिन इसके लिए लोगों की जन-जागरूकता, उनकी सामूहिक भागीदारी के साथ सख्त निगरानी भी आवश्यक है। इससे समस्या कभी विकराल रूप नहीं ले सकेगी। उन्होंने कहा कि इस समस्या के निराकरण के लिए लोगों की इच्छा शक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण पहलू हैं।

सुरक्षित और सुगम वातावरण प्रदान करने के लिए मण्डल प्रतिबद्ध : आयुक्त

जयपुर। आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने मंगलवार को मंडल के सभागार में विभागीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। बैठक में आवासन आयुक्त द्वारा वर्षाकाल की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा की गई और आवश्यक दिशा

■ बैठक में आवासन आयुक्त द्वारा वर्षाकाल की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए

निर्देश दिए गए। डॉ. रश्मि शर्मा ने वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवासन मण्डल की समस्त परियोजनाओं में सुरक्षा और सुचारु प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से क्षितग्रस्त सड़कों, खुले मैनेहोल, झूलते विद्युत बॉक्स और असुरक्षित केबल्स की शीघ्र



आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने (बीच में) ने मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली ।

मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालना करते हुए श्रमिकों और राहगीरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने विद्युत प्रबंधन को अत्यंत संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि अतिवृष्टि के दौरान मण्डल की आवासीय योजनाओं में विद्युत आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए

हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं, कंट्रोल रूम को सक्रिय रखा जाए और पूरे सिस्टम की सघन मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि वे मौके पर रहकर निगरानी करें और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। मण्डल के सभी अधिकारी तत्परता और सजगता

से कार्य करें, मण्डल अपने रहवासियों के जीवन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा , मुख्य अभियंता एचक्यू टीएस मीणा , मुख्य अभियंता प्रथम अमित अग्रवाल, मुख्य अभियंता प्रतीक श्रीवास्तव , वित्तीय सलाहकार रोहिताश यादव सहित मुख्यालय के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे व जिलों से अभियंता वीसी के माध्यम से जुड़े ।